Shodhaamrit, Vol.-2; Issue-2 (July-Dec.) 2025 : Page No.-183-185

शोधामृत

(कला, मानविकी और सामाजिक विज्ञान की अर्धवार्षिक, सहकर्मी समीक्षित, मूल्यांकित शोध पत्रिका)

ISSN : 3048-9296 (Online)
3049-2890 (Print)
IIFS Impact Factor-2.0
Vol.-2; issue-2 (July-Dec.) 2025
Page No- 183-185

©2025 Shodhaamrit
https://shodhaamrit.gyanvividha.com

उत्तम कुमार नोनिया
सहायक प्राध्यापक,
हिन्दी विभाग,पटना विश्वविद्यालय

Corresponding Author :
उत्तम कुमार नोनिया
सहायक प्राध्यापक,
हिन्दी विभाग,पटना विश्वविद्यालय

NEP 2020 के महत्त्वपूर्ण बिंदु और भाषा की चुनौतियाँ

भूमिका- भारत एक बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक राष्ट्र है, जहाँ शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान अर्जन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्रीय एकता का भी प्रतीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) ने इस व्यापक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सुधार का प्रस्ताव रखा है। इस नीति का मुख्य ध्यान भाषा के सवाल पर है, जहाँ मातृभाषा में शिक्षा को प्राथमिकता दी गई है, ताकि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास बेहतर हो सके। इसके साथ ही, तीन-भाषा सूत्र, मल्टीडिसिप्लिनरी संस्थान, और डिजिटल शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया है। हालांकि, इन सुधारों के सफल क्रियान्वयन के लिए कुछ चुनौतियाँ जैसे भाषाई विविधता, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी और अभिभावकों की मानसिकता को भी सुलझाना आवश्यक है। NEP 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक नई दिशा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

भारत एक विविधतापूर्ण राष्ट्र है जहाँ शिक्षा केवल ज्ञान अर्जन का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, संस्कृति के संरक्षण और राष्ट्रीय पहचान का आधार भी है।भारत जैसी बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक और विविधतापूर्ण सभ्यता में शिक्षा का प्रश्न कभी केवल साक्षरता या कौशल का प्रश्न नहीं रहा, बल्कि यह हमेशा भाषा, संस्कृति और पहचान से भी जुड़ा रहा है।ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी दस्तावेज़ बनकर सामने आई है। यह नीति शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर नवाचार, समावेशन और गुणवत्ता को बढ़ावा देने के साथ-साथ भाषा के सवाल को केंद्र में रखती है। यह प्रश्न कि शिक्षा किस भाषा में दी जाए — मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा या अंग्रेज़ी — भारतीय संदर्भ में महत्त्वपूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयाम लिए हुए है। इसलिए भाषा का सवाल केवल शैक्षिक नीति का भाग नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक अस्मिता से भी गहराई से जुड़ा हुआ है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षा की संरचना को पूरी तरह से पुनर्गठित किया है। पारंपरिक 10+2 व्यवस्था को हटाकर इसे 5+3+3+4 मॉडल में परिवर्तित किया गया है। इस मॉडल के अनुसार प्रारंभिक पाँच वर्षों को 'फाउंडेशन स्टेज', अगले तीन को 'प्रारंभिक स्टेज', फिर तीन को 'मध्य स्टेज' और अंतिम चार वर्षों को 'माध्यमिक स्टेज' कहा गया है। यह संरचना बाल मनोविज्ञान, विकासात्मक आवश्यकताओं और अधिगम सिद्धांतों पर आधारित है जो बच्चों के सोचने, समझने और सीखने की क्षमता को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है[1]।

NEP 2020 में एक सबसे महत्त्वपूर्ण बिंदु है कि कक्षा 5 तक (और जहाँ संभव हो वहाँ कक्षा 8 तक) शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए[2]। यह विचार इस मान्यता पर आधारित है कि बच्चा जिस भाषा को समझता है, उसी में वह सबसे बेहतर सीखता है। यद्यपि अंग्रेज़ी का ज्ञान वैश्विक स्तर पर आवश्यक है, परंतु प्रारंभिक वर्षों में मातृभाषा में शिक्षा संज्ञानात्मक विकास को अधिक प्रभावी बनाती है। यह केवल एक वैचारिक प्रस्ताव नहीं, बल्कि शोधों द्वारा सिद्ध वैज्ञानिक तथ्य है। UNESCO के अनुसार — "Children learn best in the language they speak and understand"[3]।

तीन-भाषा सूत्र, जो पहले से लागू था, NEP 2020 में लचीलापन के साथ पुनः प्रस्तुत किया गया है। इसके तहत छात्रों को तीन भाषाएँ सीखनी होंगी — जिसमें कम से कम दो भारतीय भाषाएँ होंगी। यह व्यवस्था देश की भाषाई विविधता को सम्मान देने के साथ-साथ सांस्कृतिक समावेशन को भी बढ़ावा देती है[4]। किंतु व्यावहारिक दृष्टिकोण से इस नीति के क्रियान्वयन में कई जटिलताएँ हैं। कुछ राज्यों, विशेषतः तमिलनाडु ने तीन भाषा सूत्र का विरोध किया है क्योंकि वे इसे भाषा थोपने का प्रयास मानते हैं[5]।

NEP 2020 में उच्च शिक्षा को भी पुनर्परिभाषित किया गया है। अब मल्टीडिसिप्लिनरी संस्थानों को बढ़ावा दिया जाएगा जहाँ छात्र विज्ञान, कला और वाणिज्य को एक साथ पढ़ सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए 'Academic Bank of Credits' की स्थापना की गई है जो छात्रों को लचीलापन प्रदान करता है[6]। इसके अतिरिक्त शिक्षक शिक्षा को भी सुदृढ़ बनाने हेतु 2030 तक सभी शिक्षकों के लिए चार वर्षीय एकीकृत B.Ed. अनिवार्य किया गया है[7]। मूल्यांकन प्रणाली में सुधार हेतु 'PARAKH' नामक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना की गई है, जो छात्रों की समग्र प्रगति को परखेगा न कि केवल रटकर याद किए गए तथ्यों को[8]। वहीं डिजिटल शिक्षा को सशक्त करने के लिए 'National Digital Education Architecture (NDEAR)' और 'DIKSHA' जैसे प्लेटफ़ॉर्म विकसित किए जा रहे हैं, जिससे शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया अधिक समावेशी और तकनीक-सक्षम हो सके[9]।

जहाँ एक ओर ये सभी पहलू शिक्षा की गुणवत्ता और समावेशिता को बेहतर बनाते हैं, वहीं दूसरी ओर "भाषा का सवाल" अब भी नीति की सबसे बड़ी चुनौती है। भाषाविद् नोम चॉम्स्की का कहना है — "Language is a mirror of the mind"[10]। भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं, बल्कि सोचने, कल्पना करने और अनुभव व्यक्त करने का साधन है। इसीलिए जब शिक्षा को बच्चे की भाषा में प्रस्तुत किया जाता है, तो वह सहज और प्रभावी होती है। लेकिन इसके बावजूद भारत में आज भी अंग्रेज़ी को 'अच्छी शिक्षा' और 'सफलता की कुंजी' माना जाता है। इससे मातृभाषाओं को द्वितीयक बना दिया गया है और यह दृष्टिकोण बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए बाधक बनता है[11]।

एक ओर जहाँ NEP 2020 मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देती है, वहीं व्यवहारिक स्तर पर कई समस्याएँ हैं। सबसे पहली समस्या है स्थानीय भाषाओं में प्रशिक्षित शिक्षकों की भारी कमी। दूसरी, पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण सामग्री की उपलब्धता एक गंभीर चुनौती है। तीसरी, अभिभावकों की मानसिकता — जो अंग्रेज़ी माध्यम को ही श्रेष्ठ मानती है — बच्चों को मातृभाषा में पढ़ने से रोकती है। चौथी,

रोजगार के अवसरों में अंग्रेज़ी का वर्चस्व भी इस नीति के क्रियान्वयन को सीमित कर सकता है[12]।

इसके अलावा, भाषाई विविधता को लेकर भी नीति को संतुलन बनाए रखना होगा। भारत में 22 अनुसूचित भाषाओं के अतिरिक्त 19,500 से अधिक मातृभाषा-रूप प्रचलित हैं[13]। ऐसे में सभी क्षेत्रों के लिए समान नीति बनाना एक चुनौती है। हालाँकि, NEP 2020 ने इस दिशा में 'लचीलापन' का मार्ग अपनाया है, जो एक विवेकपूर्ण निर्णय है। यह नीति राज्यों और विद्यालयों को भाषा चयन की स्वतंत्रता देकर स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार शिक्षा प्रणाली लागू करने की अनुमति देती है[14]।

नीति बहुभाषिकता को एक शक्ति मानती है। अनुसंधान बताते हैं कि बहुभाषिक छात्र अधिक रचनात्मक, अनुकूलनशील और समस्या समाधान में कुशल होते हैं[15]। यह न केवल संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से लाभकारी है, बल्कि यह छात्रों को वैश्विक नागरिक बनने में भी मदद करता है। यही कारण है कि नीति में AI आधारित अनुवाद, भाषाई प्रौद्योगिकी और डिजिटल संसाधनों के विकास की बात की गई है, जिससे सभी भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण सामग्री सुलभ हो सके।

इस संपूर्ण परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि भाषा नीति के सफल क्रियान्वयन हेतु कुछ ठोस कदम उठाए जाएँ। जैसे— स्थानीय भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण डिजिटल व प्रिंट सामग्री तैयार करना, शिक्षकों को भाषाई प्रशिक्षण देना, अभिभावकों को जागरूक बनाना, और मूल्यांकन पद्धति को भाषाई विविधता के अनुरूप ढालना। इसके अतिरिक्त बच्चों को बचपन से बहुभाषिक वातावरण देना और भाषा के प्रति सम्मान का वातावरण निर्मित करना भी आवश्यक है।

अंततः, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एक नवयुग की शुरुआत है। यह न केवल वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत की स्थिति को सुदृढ़ बनाएगी, बल्कि सांस्कृतिक मूल्यों, भाषाई अस्मिता और सामाजिक समावेशिता को भी पुनर्स्थापित करेगी। किंतु इसका सफलता पूर्वक क्रियान्वयन भाषा के सवाल को सुलझाए बिना संभव नहीं है। भाषा का सवाल दरअसल शिक्षा की आत्मा से जुड़ा है— जब शिक्षा अपनी जड़ों से जुड़ी भाषा में होगी, तभी वह समावेशी, न्यायपूर्ण और प्रभावी बन पाएगी।

संदर्भ सूची :

1. NEP 2020: Ministry of Education, Govt. of India. https://www.education.gov.in
2. NEP 2020, Section 4.11 – Medium of instruction
3. UNESCO (2003). Education in a Multilingual World
4. Three Language Formula – Kothari Commission, 1968
5. Jhingran, Dhir (2005). Language Disadvantage: The Learning Challenge in Primary Education
6. Academic Bank of Credits, UGC Guidelines 2021
7. National Curriculum Framework for Teacher Education, 2022
8. NEP 2020, Section 4.40 – PARAKH
9. National Digital Education Architecture (NDEAR), 2021
10. Chomsky, Noam (1975). Reflections on Language.
11. Devy, G. N. (2017). The Crisi Within: On Knowledge and Education in India
12. NEP 2020: Ministry of Education, Govt. of India.
13. NEP 2020, Section 4.11 – Medium of instruction
14. NEP 2020, Section 4.11 – Medium of instruction
15. Skutnabb-Kangas, Tove (2000). Linguistic Genocide in Education

•